



No 990720

संस्थाओं के निवन्धन का प्रमाण-पत्र

(चि 21, 1860)

सं. 2001-2002

संस्था
111

में इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि डा० अब्बेदकर चिन्तन

समाजिक शोध संस्थान

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ है।

आज तारीख वारह मान नूतन हजार एको पटना में मेरे हस्ताक्षर के

साथ दिया गया।

19.6.01

वासुदेव, महा लेखक, निवन्धन, गिहार, पटना।

1507000 (निवन्धन) 1 1-11-000-12-8-20,000-2-2

डॉ अम्बेदकर चिन्तन समाजिक शोध संस्थान
(डी०ए०टी०ए०आर०आई)

**का
संशोधित स्मृति-पत्र**

1. इस संस्थान का नाम : डॉ अम्बेदकर चिन्तन समाजिक शोध संस्थान होगा।

2. निबंधित कार्यालय- लातापुर कुदरा कैमूर (भुआ)

3. प्रशासित क्षेत्र- जवहन कानन वॉड नं० 2 उड़गाह महल्ला डिहरी,

4. संक्षिप्त नाम अंग्रेजी- डी० ए० टी० ए० आर० आई।

5. संस्था का कार्य क्षेत्र- सम्पूर्ण भारत।

6. अंग्रेजी नाम- डॉ अम्बेदकर थॉउट ऑफ सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट।

7. उद्देश्य- जन अनुग्रह से लोक हित।

8. (क) समाज को आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सभी तरह के उपेक्षित व्यक्तियों के समुचित विकास कि स्थापना करना के विकास की व्यवस्था करना।

(ख) वर्ष में दो बार सांस्कृतिक कार्य-क्रम का आयोजन एवं ग्रामिण कलाकारों को प्रोत्साहित करना एवं प्रशिक्षण देना।

(ग) प्रौढ़ शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, एवं समाज को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान सरकार द्वारा सशिक्षा अभियान एवं अन्य प्रकार की शिक्षा कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग देना।

(घ) महिलाओं को विभिन्न उद्योग में प्रशिक्षण दिलाकर लाभान्वित करना जैसे सिटार्ड, कढ़ाई, बुनाई, हस्तकला, कढ़ाईकारी, बुनाई, पेंटिंग बनाना तथा फल संरक्षण आदि।

(ङ) जन मानस की सदृश्यताओं को प्रोत्साहन देने वाली उल्लेखनीय निष्ठापूर्ण मान्य हित संबंधीत कार्यों को बढ़ावा देना वाली सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाले पत्रिकाओं का प्रकाशन।

9. (अ) संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं को रियायती दर पर विक्रय हेतु पहल करना।

(आ) महापुरुषों के जीवन चरित्र का प्रचार-प्रसार करना।

(इ) उत्तम खाद एवं उत्तम बीज की-उपलब्धता में किसानों को प्रशिक्षण कि व्यवस्था करना तथा बायोगैस संयंत्र की स्थापना करना।

(उ) ग्रामिण श्रमिकों को श्रम अधिनियमों से परिचित करना।

10. (क) पशु-चिकित्सा के लिए टीकाकरण एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना।

(ख) ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना।

(ग) रपुश्यता उन्मूलन, दहेज प्रथा उन्मूलन, जाति प्रथा एवं सती प्रथा जैसी बुराइयों को उन्मूलन में सहयोग करना।

(घ) - - - - - जाति हेतु शिविर सम्मेलन, प्रदर्शनी या जनसंपर्क अभियान का आयोजन करना।

(ङ) ग्रामीण एवं शहरी लोगों के विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तकला उद्योग, ग्रह उद्योग, रोजगार, जल, आग, अपलब्ध कर कर युवाओं के लिए स्वरोजगार अनाद्य हेतु स्थापना करना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(च) पंचायतीराज व्यवस्था एवं नगरपालिका अधिनियम को लोकप्रिय तथा प्रभावी बनाने हेतु कार्य करना।

(छ) पूर्ण नशावर्दी अभियान कार्य-क्रम के अंतर्गत नशा से निपट गजदूर एवं जनसधारणको इरादे होने वाली हानि से परिचित करना तथा शराब कि आदत को त्यागने हेतु साहित्य प्रकाशित एवं इससे बचने के लिये उपायों का प्रचार-प्रसार करना।

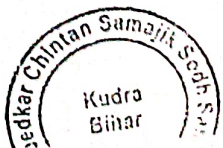
(ज) सेमित एवं वनवासियों तथा आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए संबंध सहयोग करना।

11. (क) समाज में पिछड़ी जातियों दलितों, महिलाओं अल्पसंख्यकों अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जनजाति के कल्याण के लिये योजनाओं का संचालन करना।

(ख) - - - - - नियंत्रण एवं परिवार कल्याण हेतु योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना।

(ग) लोगों कि हरीयाली एवं पुरा तत्व विशिष्टता का सर्वेक्षण एवं सन्वर्धन करना।

(घ) जलउद्योग एवं आंतरिक संसाधन के समुचित उपयोग हेतु विभिन्न प्रकार के कार्य क्रमों का क्रियान्वयन करना।



- 

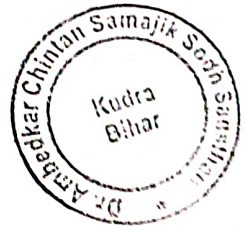
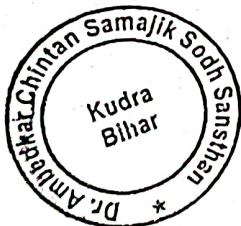
23. कार्यकारीणी समिति को अग्रणीकरण एवं कार्य:-
संस्था के समि कर्मा कर संपादन विधित्त करना एवं प्रस्ताव परीत करना संस्था का चल-चमल संपत्ती का उत्तर
दायी होगा। उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्यकरण तथा संपत्ती का महत्त्व करना है, प्रमाण-पत्र जारी करना
24. संस्था के अधिकार एवं कर्तव्य :-
संस्था के आग-आग सेवा पर विचार कर स्वीकृति देना । समिति को पदाधिकारीयो एवं सदस्यों का निर्वाचन करना
आयस के ताल से अन्य विवरण पर विचार करना।
25. बैठक के सुचना :-
कार्यकारीणी की बैठक की सुचना 7 दिन पूर्व दी जायेगी एवं आवश्यक बैठक की सुचना 48 घंटे पूर्व दि जायेगी ।
26. कानूनी कार्यवाही :-
संस्था के द्वारा किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही सचिव के पद नाम से होगी ।
27. विधि का अंकेशन :
यदि निबंधन महानिरीक्षण चाहे तो किसी भी संस्था का अंकेशन किसी प्राधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेड से करा सकते
है, जिसका खर्च संस्था को ही वहन करना होगा।
28. संस्था का विघटन :
संस्था के विघटन के पूर्व सरकार से अनुमति प्राप्त कर यह विघटित होगा एवं आम सभा के 3/5 सदस्यों की
सहमती से सामान्य उद्देश्य वाली दुसरी संस्था या सरकार को सारी संपत्ति दे दी जायेगी।
29. अन्याय:
संस्था का अन्य कार्य जिसके संबंध नियमावली में उपलब्ध नहीं हो पाया है वह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट
21/1860 के अंतर्गत किया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह इस नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है।

B. Pandey
अध्यक्ष

श्यामा
कोषाध्यक्ष

डा. अम्बेकर चिन्तन
सचिव



८७

डॉ० अम्बेदकर चिन्तन समाजिक शोध संस्थान की संशोधित

नियमावली

1. संस्थान का नाम :-

डॉ० अम्बेदकर चिन्तन समाजिक शोध संस्थान ।

2. संस्थान का निम्नलिखित कार्यालय

लात्तापुर गुरुदास कौमूर (भागुआ)

3. पञ्चासनीक कार्यालय

नन्दा नारायण चौक नं० 23 इंदौर महत्वा दिवरी

4. संस्थान का नाम अंग्रेजी में

डी०ए०पी०एस०आर०आई०

5. संस्थान का क्षेत्र

संमपूर्ण भारत

6. संस्थान का उद्देश्य

जन अनुग्रह से लोकहित ।

7. संस्थान की परिभाषा

(क) संस्थान से अभिप्राय है।

डॉ० अम्बेदकर चिन्तन समाजिक शोध संस्थान

(ख) समिति से अभिप्राय है- संस्थान की कार्यकारीणी समिति।

(ग) पदाधिकारी से अभिप्राय है - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव

कोसाध्यक्ष

(घ) वर्ष से अभिप्राय है- एक जनवरी से 31 दिसम्बर तक

(ङ) एकट से अभिप्राय है - संस्थान अधिनियम 21, 1860

8. सदस्यता :-

कोई भी स्त्री एवं पुरुष जो भारत का नगरिक होगा-जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होगी तथा संस्थान के नियमों एवं उद्देश्यों का पालन करेगा संस्थान का सदस्य बन सकता है। सदस्य बनने हेतु निहित प्रपत्र में आवेदन पत्र देना होगा। जिसकी स्वीकृती या अस्वीकृती कार्यकारीणी समिति द्वारा प्रदान कि जायेगी तथा प्रत्येक सदस्य को 51 रुपये का प्रवेश शुल्क एवं 21 रुपये का वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।

9. सदस्यता के प्रकार कि होगी :-

(क) आजिवन सदस्यता - जो आजिवन सदस्य बनना चाहेगा उसे 5011 रुपये का प्रवेश शुल्क अदा करवा पड़ेगा।

(ख) कियाशिल सदस्यता - जो सदस्य प्रवेश शुल्क, वार्षिक प्रवेश शुल्क अदा करते हैं ये वे कियाशिल सदस्य होंगे।

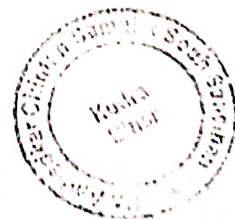
10. सदस्यता से वंचित करना :-

(क) स्वयं त्याग पत्र देने पर मृत्यु होने पर, पागल होने पर या दिवालिया होने पर ।

(ख) संस्थान के नियम एवं उद्देश्यों का उल्लंघन करने पर ।

(ग) सदस्यता शुल्क रागस पर नहीं देने पर ।

(ङ) अभिप्राय प्रस्ताव पारित होने पर।



(द्वि) जिस कारण सदस्य समिति की समाप्ति तीस बैठक के अनुपस्थित होने पर।

11. संस्था के द्वारा निर्धारित दिने जसे सदस्य की संख्या का कार्यकारी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत के मत पर

एक निर्देशित दिने जसे सदस्य को हटित्य से पूर्व जल्दी की पूर्णगति में होने जैसे का प्रमाण पत्र देने पर दोबारा सदस्यता में ला सकयी है। दोबारा सदस्यता प्राप्ति के दिने उसके उचित क्षमाना आदि अदा करया होगा।

12. संस्था में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :-

अध्यक्ष	- एक	उपाध्यक्ष	- एक
सचिव	- एक	उपसचिव	- एक
कोषाध्यक्ष	- एक	सदस्य	- 15

13. कार्यकारीणी समिति का भव्य :-

(क) कार्यकारीणी समिति कम से कम न्यारह सदस्यो की होगी।

(ख) समिति की पदाधिकारी एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा किया जायेगा।

(ग) समिति का कार्यकाल इताल का होगा।

(द्वि) अगर समिति में कोई में कोई पद रिक्त हो तो शेष औषी के लिये उक्त पद पर किसी सदस्य को समिति मनोनित कर सकयी है। किन्तु वार्षिक बैठक में विधिवत चुना करा लेना होगा।

14. संस्था की रूप रेखा :-

(क) राष्ट्रीय कार्यकारीणी समिति।

(ख) प्रांतीय कार्यकारीणी समिति।

(ग) जिला कार्यकारीणी समिति।

(घ) प्रखण्ड कार्यकारीणी समिति।

(ङ) ग्राम पंचायत कार्यकारीणी समिति।

15. कार्यकारीणीयो के अधिकार एवं कर्तव्य :

अध्यक्ष:-

(क) संस्था की प्रत्येक बैठक का अध्यक्षता करना।

(ख) बैठक बोलाने हेतु सचिव को निर्देश देना।

(ग) अध्यक्ष का कार्य काल पाँच साल का होगा।

(घ) आवश्यकता पड़ने पर अपने निर्णायक मत द्वारा किसी विषय में निर्णय लेना।

(ङ) कार्यवाही पंजी में अपना हस्ताक्षर करना एवं जिला प्रखण्ड, पंचायत के इकाइयों का गठन कार्यकारीणी के राय से

करना।



उपाध्यक्ष :-

- (क) अध्यक्ष की अनुपस्थिती की बैठक को अध्यक्षता करना ।
- (ख) अध्यक्ष के अनुपस्थिती में सारे कार्यों का संपादन करना ।

सचिव :-

- (क) बैठक का आयोजन करना ।
- (ख) बैठक के कार्यवाही की कार्यवाही पंजी में लिखना व अध्यक्ष का हस्ताक्षर करवाकर अपना हस्ताक्षर करना ।
- (ग) कार्यालय की देख-रेख कार्यवाही पंजी एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।
- (घ) संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सभी परिश्रम करना, संस्थान के पुर्व अनुगति के बिना 500/- रुपया तक व्यय करना ।
- (ङ) संस्था का पत्रचार एवं आय - व्यय, रख - रखाव और निगानि करना तथा रागय पर अंकक्षण करना ।
- (च) सचिव का कार्यकाल 5साल का होगा एवं जिला प्रखण्ड पंचायत की ईकाइयों का देख-रेख करना ।
- (छ) अधिक आय-व्यय पर नियंत्रण रखना ।
- (ज) संस्थान के उद्देश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रधान कार्यालय का स्थानान्तरण राज्य के अंदर या बाहर देश के किसी भी हिस्से में करना तथा उसकी सुचना निबंधन कार्यालय को 15 दिनों के भितर देना होगा । साथ ही शाखा या उपशाखा को राज्य के अंदर या बाहर कहीं भी स्थापित करना ।

उप सचिव:-

- (क) सचिव के अनुपस्थिति में उनके सभी कार्यों को करना ।
- (ख) सचिव को सहयोग देना तथा संस्था के कार्यों में सहयोग करना ।

कोषाध्यक्ष:-

- (क) संस्था के सभी कोशों को बैंक में जमा करना तथा निकालना एवं उनका पुरा-पुरा हिसाब किताब रखना । कोषाध्यक्ष का कार्यकाल पाँच साल का होगा ।
- (ख) आय-व्यय को सचिव के द्वारा बैठक में रखना ।
- (ग) गन्तव्यता शुल्क तथा चंदा प्राप्त कर रशीद देना । एक बही में अंकित करना । संस्था के कोष का अध्यक्ष एवं सचिव और कोषाध्यक्ष के किन्हीं दो के हस्ताक्षर से बैंक में जमा करना एवं राशी की निकाशी करना होगा ।



14. संस्था का वित्तीय वर्ष : संस्था का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष की दिनांक 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक चलता होगा।
15. संस्था का वित्तीय साधन (आय स्रोत) :
सदस्यों द्वारा प्रदाता, सदस्यता शुल्क केन्द्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर आय आबुदान तथा अन्य निदेशी संस्थाओं जैसे इन्सुरेण्ड आदि से सहयोग तथा आयुदान एवं आरम्भिक व्यक्तियों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा दान आदि तथा राज्य-स्तर पर संस्था द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विद्यालय में आय प्राप्त करना इत्यादि संस्था के वित्तीय साधन के स्रोत होंगे।
16. संस्था के कौशल :
प्रत्येक बैठक का कौशल कुल सदस्यों का 1/3 होगा। कौशल के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी और पुनः निर्धारित बैठक के लिए कौशल की आवश्यकता नहीं होगी। नियमित बैठक का निर्णय सर्वमान्य होगा।
17. संस्था का पंजीकरण :
संस्था का पंजीकरण केवल राज्य स्तर पर ही होगा। जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत इकाई संस्था का राज्य स्तर की शाखाएँ समझी जाएंगी। जरूरत पड़ने पर कार्यक्षेत्र बढ़ाया जा सकता है।
18. पंजीकरण का निरीक्षण :
संस्था की सभी निबंधित कार्यालय में रहेगी। जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेख पंजी, कार्यवाही पंजी सदस्यता पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं।
19. संस्था के संविधान में परिवर्तन / संसोधन :
संस्था के संविधान में संसोधन राज्य कार्यकारणी समिति के 3/5 सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा। इसकी सुचना रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज को एक्ट 21, 1860 के अनुसार भेज दी जायेगी।
20. संस्था का कोष :
संस्था की सभी इकाइयों द्वारा एकत्रीत कोष में से प्रत्येक इकाई में 40 प्रतिशत को छोड़कर शेष 60 प्रतिशत कोष राज्य कोषाध्यक्ष के पास प्रत्येक माह में जमा कर दिया जायेगा। जिसको कोषाध्यक्ष संस्था के नाम से बैंक में जमा करेगा।
21. बैंक से पैसा निकालने का अधिकार :
अध्यक्ष, एवं कोषाध्यक्ष, में से किसी एक एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाक घर में खाता खोला जाएगा। जिन्हें संस्था का उद्देश्य के मुताबिक पैसा निकालने का अधिकार होगा।
22. संस्था की बैठक :
संस्था की सभी स्तर की इकाइयों की बैठक प्रत्येक स्तर की इकाई के अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक स्तर के सचिव के साथ से.वर्ष में कम से कम एक बार बुलाई जाएगी। कार्यकारणी की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी एवं आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष की जनवरी माह में होगी। तथा आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती हैं।



23. कार्यकारीणी समिति के अधिकार एवं कार्य:-
संस्था के सभी कार्य कर संपादन विधिवत करना एवं प्रस्ताव परीत करना संस्था का चल-अचल सम्पत्ती का उत्तर दायी होगा। उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्यकरना तथा उपकरण का गठन करना है, प्रमाण-पत्र जारी करना
24. आम सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-
संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना । समिति के पदाधिकारीयों एवं सदस्यों का नियंत्रण करना आम्जन के साथ से अन्य विषय पर विचार करना।
25. बैंक रिज सुचना :-
कार्यकारीणी की बैंक की सुचना 7 दिन पूर्व दी जायेगी एवं आवश्यक बैंक की सुचना 48 घंटे पूर्व दी जायेगी ।
26. कानूनी कार्यवाही :-
संस्था के द्वारा किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही सचिव के पद नाम से होगी ।
27. विधि का अंकेक्षण :-
यदि निबंधन महानिरीक्षण चाहे तो किसी भी संस्था का अंकेक्षण किसी प्राधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेड से करा सकते है, जिसका खर्च संस्था को ही वहन करना होगा।
28. संस्था का विघटन :-
संस्था के विघटन के पूर्व सरकार से अनुमति प्राप्त कर यह विघटित होगा एवं आम सभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से उद्देश्य वाली दुसरी संस्था या सरकार को सारी सम्पति दे दी जायेगी।
29. अन्याय:-
संस्था का अन्य कार्य जिसके संबंध नियमावली में उपलब्ध नहीं हो पाया है वह रोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21-1960 के अंतर्गत किया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह इस नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है।

B. Porely
अध्यक्ष

श्रीधर
कोषाध्यक्ष

श्रीधर कुमार
सचिव

